

(Public Budget)

सार्वजनिक/लोक वजट को अर्थपूर्ण ढंग से परिभाषित करने हेतु इसके निम्न-सहित मुख्य आयामों की जानकारी दितकर समझी जाती है-

2020

1) सार्वजनिक वजट सरकार द्वारा वित्तीय साधन जुटाने तथा व्यय करने का एक विस्तृत और मद-वार व्यय होता है। किसी समय वजट को इसी संकुचित अर्थ में परिभाषित किया जाता है। यह व्यय एक पूर्वनिश्चित कालावधि (सामान्यतः 1 वर्ष) के लिए होता है। वजट के लागू होने की तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ही इसे संसद द्वारा अन्य संबंधित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष पारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी प्रतिबंधनों के अंतर्गत सरकार वित्तीय प्राप्तिओं की कसौटी और उनके संचितरण की पूर्वानुमति प्राप्त करती है।

2) एक आधुनिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्राप्तिओं एवं व्यय संबंधी निर्णय व्यवस्थित ढंग से आँकड़ों के अनुसार जैगी मूलतः सरकार द्वारा स्क्रिप्ट संसाधन समाज की धरोहर होते हैं। और इसका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि इनका किसी प्रकार से अपव्यय न होने दे। इसके अतिरिक्त वजट की सभी मदों का परस्पर गहरा संबंध होने के कारण उनका रूप-आकार सरकार की नीति-समूह के अनुरूप होना चाहिए। अतः वैधानिक प्राधिकरण को उपयुक्त जानकारी देने और अपनी नीति-समूह से अवगत करने हेतु वजट में वित्तीय आँकड़ों के कई सेट रहते हैं। उदाहरणार्थ भारत में इन आँकड़ों के चार सेट रहते हैं, अर्थात्-

- (i) गत वर्ष के वास्तविक आँकड़े (actuals for the previous year)
- (ii) चालू (अर्थात् समाप्त होने) वर्ष के लिए पारित किए गए आँकड़े, अर्थात् 'वजट अनुमान' (budget estimates for the current/outgoing year)
- (iii) चालू वर्ष के अनुमानित वास्तविक आँकड़े, अर्थात् 'संशोधित अनुमान' (revised estimates for the current/outgoing year)
- (iv) आने वाले वर्ष (अर्थात् विचाराधीन वार्षिक कालावधि) के लिए प्रस्तावित

(2)
 अनुमान अर्थात् 'बजट अनुमान' (Budget estimates for the incoming year) इस चौथे भाग में भी गद्य-वार प्रस्तावित व्यय राशियों के आंकड़ों का सौट तथा प्राप्तियों के अनुमानों के दो सौट होते हैं। प्राप्तियों के पहले सौट में वर्तमान (existing) कर-दौंचे को गणनास्थित रखते हुए अनुमानित सशुद्ध राशियों (estimates without 'budgetary proposals') दर्शाई जाती हैं; तथा दूसरे सौट में 'बजट-प्रस्तावों' (अर्थात् कर-दौंचे एवं अन्य नीतियों आदि में प्रस्तावित संशोधनों) के परिणामस्वरूप भविष्य अनुमान (estimates with 'budgetary proposals') दर्शाए जाते हैं।

③ इस प्रकार लोक बजट के माध्यम से सरकार वेद्य, समाज तथा अर्थव्यवस्था के समस्त समस्याओं, तब्यों, लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति की संभावनाओं से संबंध अपना मूल्यंकन और नीति-समूह प्रतिबिम्बित करती है।

④ बहुधा पालू वर्ष के 'बजट अनुमानों' (budget estimates, B.E.) तथा 'संशोधित अनुमानों' (revised estimates, R.E.) में अंतर रहता है। बजट में भ्रमासंभव इसके कारणों पर प्रकाश डाला जाता है।

⑤ सामान्यतः शार्वजनिक बजट की कुछ व्यय मदों के लिए सरकार कमनीतौर पर वाद्य होती है तथा उनके लिए साधन पुनर्न के पश्चात् ही बीच व्यय मदों पर ध्यान दे सकती है। कुछ निर्दिष्ट साधन-प्राप्तियों कुछ निर्दिष्ट व्यय मदों के लिए पूर्वसंकेतित पूर्वसंकेतित (earmarked) भी हो सकती हैं।

⑥ यह भी संभव है कि बजट की दो अथवा दो से अधिक भागों में वैधानिक प्राधिकरण की प्रस्तुत किया जाए। ऐसा कई कारणों से हो सकता है—

(i) देश में बहुस्तरीय सरकारें होने पर यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों के बजट अलग से उनके वैधानिक प्राधिकरणों को पारित करने हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) सरकार के किसी एक स्तर पर भी बजट की खंडों में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ भारत में केन्द्रीय सरकार बजट में से 'रेलवे बजट' का खंड 'सामान्य बजट' (अर्थात् 'मुख्य बजट') (General or Main

(3)
(Budget) से पूर्व तथा अलग से संसद के समक्ष रखा जाता है।

(ii) कमी-कमर, चुनाव अथवा किसी अन्य कारण से भी वार्षिक वित्त बजट सामान्य कालावधि (अर्थात् वित्त वर्ष) से कम कालावधि के लिए वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष आता है तथा वर्ष के बीच भाग के लिए बजट का शेष खंड खंड वाद में पारित करने की धारी आती है।

(iv) इसी प्रकार वर्ष के दौरान (अर्थात् वित्त की कालावधि के अंतर्गत) सरकार को किन्हीं कारणों से अतिरिक्त भावनों की अथवा अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसकी पूर्ति हेतु वह एक पूरक बजट (Supplementary Budget) तैयार करती तथा पारित कराती है। पूरक बजट की आवश्यकता के कई कारण हो सकते हैं; जैसे कि सरकार के अपनी ७ कार्यकलापों और नीति में संशोधन, प्राकृतिक प्रकोप, तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन आदि।

५) बजट का मर्दा तथा मर्दा-वर्गों में वित्तवा देश के कानूनी ढाँचे तथा लेखांकन पद्धति (accounting system) पर निर्भर करता है। इस अन्विष्ट वर्गीकरण के साथ-साथ बजट को अर्धपूर्ण बनाने तथा उसके प्रभावों का सही अनुमान लगाने के लिए वित्तीय मर्दा को केवल प्राप्तियों और संचितियों के अतिरिक्त अन्य आयों पर भी वर्गीकृत किया जाता है, जिनकी व्याख्या उस अध्याय में वाद में की गई है। ध्यानयोग्य है कि बजट के संस्था राजस्य और पूंजी खातों (revenue and capital accounts) में वर्गीकरण की प्रथा बहुत पुरानी है; तथा इसके अतिरिक्त नित नए प्रकार के वर्गीकरणों को अपनाया जा रहा है।

६) प्रत्येक सरकार के समक्ष एक उद्देश्य-समूह रहता है जिसके तदनुसंग वह अपनी नीतियों और कार्यकलापों का चुनाव करने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में बजट एक दोहरी भूमिका निभाता है। वित्तीय नीतियों सरकार के समग्र नीति-समूह का एक प्रभावी और अभिन्न अंग होती है; तथा इनसे इसकी सभी नीतियों और कार्यकलापों का वित्त-पोषण भी होता है।